प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com

swarajindianews swarajindianews

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

स्वराज इंडिया

दैनिक सांध्यकालीन

कानपुर, मंगलवार, 07 अक्टूबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 264, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

राम को गाली देने वाले वाल्मीकि का अपमान करते हैं: मुख्यमंत्री

» Pg12

इनसाइड बेवजह लाठीचार्ज करने में एसपी ने तीन पुलिसकर्मियों... » Pg09

दोस्ती, ब्लैकमेलिंग और मौत की सुपारी का खेल

जिसे बहन मानकर बंधवाई राखी, उसने दी बेटे को मौत

पिता ने खोले रिश्तों को कलंकित करने वाली पूजा के कई राज, पुलिस ने नेपाल भागने की जताई आशंका

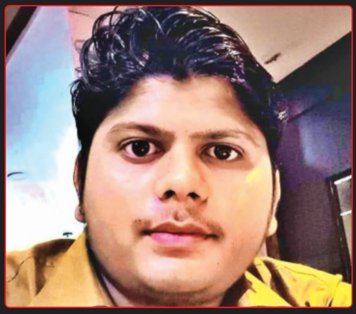

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

अलीगढ़। अलीगढ़ में बाइक शोरूम स्वामी अभिषेक गुप्ता की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। बाइक शोरूम स्वामी अभिषेक के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिषेक गुप्ता के पिता नीरज गुप्ता ने कहा है कि वह पूजा शकुन पांडेय से राखी बंधवाते थे। तीन साल तक इस रिश्ते को कायम रखा लेकिन पूजा ने रिश्ते को कलंकित किया। इसलिए पिछली दो बार से राखी नहीं बधवाई। अभिषेक के भाई आशीष ने बताया कि पिता जी विदाई के रूप में 5100 रुपये देते थे। उसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं भांप पाया। इधर, सोमवार को एसएसपी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रयासों से वह संतुष्ट हैं। पुलिस ने भरोसा दिया है कि पूजा जल्द पकड़ी जाएगी।

अभिषेक गुप्ता की हत्या के बाद परिवार ने सोमवार तक पूजा को न पकड़े जाने पर आत्मदाह का ऐलान किया था। सोमवार को एसएसपी व एएसपी से मुलाकात के बाद नीरज गुप्ता ने बताया कि पुलिस ठोस प्रयास कर रही है। हमें आस है कि जल्द पुलिस पूजा को पकड़ लेगी। जब उनसे पूजा शकुन से अब तक राखी बंधवाने के सवाल पर बात हुई तो बताया कि वह पूजा को छोटी बहन के रूप में देखते थे।

पूजा शकुन के अधिवक्ता व अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र पाल सिंह ने पुलिस पर दबाव में कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जेल में मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सोमवार को वह अशोक पांडेय से मुकदमे के सिलसिले में मिलने पहुंचे तो उन्हें पहले टरकाने का प्रयास हुआ।

अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज

पूजा शकुन के अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में दायर की गई है। इस पर आज मंगलवार को सुनवाई की तारीख नियत है। आज पुलिस स्तर से पूजा शकुन का क्राइम रिकॉर्ड व इस मुकदमे की अब तक की केस डायरी भी पेश की जाएगी।

पूजा शकुन के घर लगातार निगरानी रखे हुए है पुलिस

पूजा शकुन कहीं नेपाल तो नहीं भाग गई, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीमों ने अब पिछले दस दिन से टोल-राज्यों के बॉर्डरों पर सीसीटीवी देखना शुरू कर दिया है। अलग-अलग दिशाओं में पुलिस को लगाया गया है। चूंकि, उसके पास पासपोर्ट नहीं है इसलिए पुलिस नेपाल जाने का अंदेशा जता रही है।

पूजा शकुन की तलाश में पुलिस यूपी के कई जिलों के साथ-साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड के संभावित ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। सभी धर्मस्थल वाले नजदीकी राज्यों को भी पूजा के फोटो व मुकदमे में 25 हजार का इनाम होने की सूचना भेज दी गई है। अन्य राज्यों की पुलिस के जरिये टोल व बॉर्डर नाकों पर दिखवाया जा रहा है।

इसके अलावा बचपन से लेकर अब तक के ठिकानों कायमगंज, हिसार, सहारनपुर, रामपुर में भी परिचितों के विषय में विवरण जुटाया जा रहा है। इधर, पुलिस की एक टीम को पूजा शकुन के खातों व संपत्तियों की डिटेल निकलवाने में लगाया गया है, ताकि यह जानकारी रखी जा सके कि कहीं वह फरारी में किसी तरह का लेनदेन या संपत्ति से जुड़ा अन्य प्रयोग तो नहीं कर रही। पूजा व अशोक पांडेय के अलावा उनके परिचितों की गाड़ियों के नंबर आदि की डिटेल निकलवाई जा रही है। उन नंबरों को भी सभी जगह भेजा जाएगा। हालांकि परिवार के सभी वाहन घर पर ही खड़े हैं।

पूजा शकुन को भाजपा और संघ का था घमंड

महामंडलेश्वर बनने के बाद पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करते थे, जिनमें भाजपा और संघ के बड़े नेता भी शामिल होते थे। शूटर मोहम्मद फ़ज़ल ने पुलिस को बताया कि उसे पूजा शकुन पांडे ने भरोसा दिलाया था कि अगर कोई मुश्किल आई तो वह अपने संपर्कों से उसकी मदद करवाएंगी।

आईजी पुलिस वाई पूरन कुमार ने मारी गोली, मौत

» चंडीगढ़ (हरियाणा), एजेंसी।

पंजाब व हरियाणा की राजधानी में मंगलवार को बड़ी घटना हुई है। यहां हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। घटना सेक्टर-11 की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंची है। जानकारी मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी, सीएफएसएल और फोरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई है।

जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस के एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। आईजी वाई पूरन कुमार की कुछ दिन पहले रोहतक के सुनारिया में तैनाती हुई थी। उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित अपनी कोठी में सुसाइड किया है। वाई पूरण कुमार की पत्नी पी अमनीत कुमार विदेश दौरे पर हैं। आईएएस पी अमनीत कुमार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री राव नरवीर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी जापान में हैं।

आप नेताओं को पुलिस ने घर-दफ्तर पर रोका

बरेली बवाल: संजय सिंह बोले- तानाशाही के खिलाफ आवाज नहीं रुकेगी

» लखनऊ, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राजधानी लखनऊ से बरेली जाने के लिए निकला तो कार्यालय गेट पर पुलिस से सामना हुआ। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें जाने से रोका। लेकिन, आप कार्यकर्ता जाने पर अड़े रहे। इस पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान देखी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

पुलिस ने आप नेता नदीम अशरफ और सरबजीत मक्कड़ को हाउस अरेस्ट किया। जबकि, इमरान लतीफ को गोमती नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर रोक लिया गया। पार्टी नेताओं के बरेली जाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क था। पार्टी कार्यालय पर सुबह से ही पुलिस तैनात हो गई।

दूसरी तरफ पूर्व विधायक दिलीप पांडेय अपने दिल्ली आवास से दोपहर 2 बजे बरेली के लिए निकलेंगे। हालांकि, उनको भी पुलिस जाने देगी, इसकी कम संभावना है। वहीं पार्टी ने इस मामले में प्रदेश सरकार की नीति को दमनकारी बताते हुए, आगे भी अपना विरोध जारी रखने की घोषणा की है।

आप कार्यकर्ताओं को कार्यालय और घर में रोका गया तो सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि न कोई आदेश है, न कोई कानून। यूपी पुलिस मनमानी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाना भी बंद कर रही है। बरेली के पीड़ितों से मिलने की भी इजाजत नहीं है। यहां नफरत फैलाने और गुंडागर्दी करने की खुली छूट है। सजंय सिंह ने आगे लिखा कि बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष इमरान लतीफ, अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल और मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे, अभिषेक सिंह को पुलिस ने बिना किसी आदेश के रोका है। तानाशाही के खिलाफ आप की आवाज को रोका नहीं जा सकता है।

फील्ड गन फैक्टरी कर्मियों का धरना

प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश,बड़े आंदोलन की चेतावनी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ न मिलने से नाराज फील्ड गन फैक्टरी के कर्मचारियों ने मंगलवार को मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रबंधन हठधर्मिता दिखा रहा है, और चेतावनी दी है कि यदि इस महीने के अंत तक बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया गया, तो नवंबर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

कानपुर में फील्ड गन फैक्टरी कानपुर के प्रबंधन के संवेदनहीन और हठधर्मिता पूर्ण रवैये के विरोध में मंगलवार को निर्माणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण समिति कानपुर के तत्वावधान में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसे फैक्टरी की सभी यूनियनों और एसोसिएशनों ने पूर्ण समर्थन दिया।

समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार सचान ने बताया कि विवाद नोशनल इंक्रीमेंट के लाभ को लेकर है। 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने का आदेश कैट इलाहाबाद ने जनवरी 2022 में दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने जनवरी 2023 में निर्माणी की अपील को खारिज करते हुए बरकरार रखा था।

कर्मचारियों को नहीं दिया है लाभ

रक्षा मंत्रालय और आयुध निदेशालय ने भी नवंबर/दिसंबर 2023 में न्यायालय के आदेश को लागू कर पेंशनरी लाभ देने का निर्देश जारी कर दिया था।

सचान ने आरोप लगाया कि अन्य सभी निर्माणियों में यह लाभ दिया जा चुका है, लेकिन फील्ड गन फैक्टरी प्रबंधन ने आज तक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया है, जिसके कारण उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा।

बड़े आंदोलन की चेतावनी

समिति के उपाध्यक्ष छबिलाल यादव ने सभा को संबोधित करते हुए प्रबंधन को चेतावनी दी।

उन्होंने कहा कि यदि निर्माणी प्रशासन इस माह के अंत तक कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ प्रदान कर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं करता है, तो समिति नवंबर माह में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी निर्माणी प्रशासन की होगी।

महिला लिपिक का हाथ पकड़ने वाले डॉक्टर को प्रशिक्षण से किया बाहर

कानपुर। कांशीराम अस्पताल के सीएमएस डॉ. नवीनचंद्रा ने बताया कि डॉ. शिवम मिश्रा उनके पास आया था। बहुत रो-गा रहा था। कह रहा था कि अब नशा छोड़ देगा। वह लखनऊ के निरवाना नशा मुक्ति केंद्र में नशे की लत छोड़ने के लिए भर्ती हो गया है।

कानपुर में अनेस्थेसिया विभाग में वेंटिलेटर का प्रशिक्षण लेने आए डॉक्टर के नशे की हालत में महिला लिपिक का हाथ पकड़ने के मामले में कार्रवाई की गई है। आरोपी डॉक्टर को प्रशिक्षण से बाहर कर दिया गया है। डॉक्टर की तैनाती कांशीराम अस्पताल में है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने कहा कि इस तरह की घटनाएं होंगी तो बाहर के अस्पताल के डॉक्टरों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। डॉ. काला ने प्रमुख सचिव और महानिदेशक को पत्र भेज मामले की जानकारी दी है।आरोपी डॉक्टर लखनऊ के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हो गया है। महिला लिपिक का हाथ पकड़ने का मामला शुक्रवार का है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अनेस्थेसिया विभागाध्यक्ष डॉ. अपूर्व अग्रवाल ने मामले की लिखित शिकायत प्राचार्य डॉ. संजय काला से की थी। इस पर प्राचार्य ने कड़ा रुख अपनाते हुए पहले कांशीराम अस्पताल के सीएमएस डॉ. नवीन चंद्रा को पत्र लिखकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा।

20 को मनाई जाएगी दीपावली, तिथियों को लेकर कोई संशय नहीं

» कुछ पंचांगों में तिथि की गड़बड़ी से बनी असंजस की स्थिति, काशी विद्वत परिषद ने दूर किया भ्रम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर। सनातन परंपरा में प्रकाश के महापर्व दीपावली का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। धन की देवी मां लक्ष्मी और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजा से जुड़ा यह पावन पर्व 20 या फिर 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं कुछ लोग दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच होने वाले एक दिन के गैप को लेकर परेशान है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की सभी सही तारीख को लेकर जो कन्फ्यूजन आपके मन में है, उसे काशी विद्वत परिषद ने दूर करते हुए एक मत से सही तारीखें घोषित कर दी हैं. आइए दिवाली समेत सभी पर्वों की सही तारीखें ज्योतिष एवं शास्त्रीय नियमों के आधार पर जानते हैं।

काशी विद्वत परिषद ने दूर किया कन्फ्यूजन

काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री प्रो. राम नारायण द्विवेदी के अनुसार सूर्य सिद्धांत के अनुसार ही पंचांग निर्माण की हमारी ऋषि परंपरा रही है। धर्म शास्त्र के अनुसार ही हमारे निर्णय पूर्णतः फलित होते हैं। इसी को आधार मानते हुए देखें तो 20 अक्टूबर को दोपहर 02:45 मिनट पर अमावस्या लग रही है। हमारे यहां प्रदोष व्यापिनी अमावस्या ही दीपावली पर ग्राह्य होती है जो कि अगले दिन 04:15 बजे तक रहेगी। ऐसे में धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा।

एकमत होकर पर्वों पर निर्णय करेंगे

प्रो. राम नारायण द्विवेदी के अनुसार कुछ पंचांग में भ्रमवश दिखाया गया है कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या 21 अक्टूबर 2025 तक जा रही है जो कि गणितीय दृष्टि से देखें तो कहीं से भी संभव नहीं हो रहा है। उन पंचांगकारों से विमर्श करने के बाद तय हुआ है कि 2026 से हम एकमत होकर पर्वों पर निर्णय करेंगे। ताकि सनातनी परंपरा में पर्व की तिथि को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय न रहे।

20 को दोपहर 02:45 बजे से अमावस्या

20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 02:45 मिनट पर अमावस्या लग रही है। जो कि अगले दिन प्रातः 04:15 बजे तक रहेगी. ऐसे में धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा.

कानपुर में इतिहास रच गए आईपीएस अखिल कुमार

अखिल कुमार का बयान

मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे कानपुर के पुलिस आयुक्त के रूप में सेवा का अवसर दिया। शहर की मूलभूत समस्या माफिया थे, जिन्होंने व्यवस्था को दीमक की तरह चट कर दिया था। हमारी टीम ने दिखाया कि सही मार्ग पर चलकर आपराधिक तत्वों को नेस्तनाबूत किया जा सकता है। ऑपरेशन दिव्य दृष्टि, ऑपरेशन त्रिनेत्र और ऑपरेशन महाकाल ने शहर को नई दिशा दी और जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

» 'ऑपरेशन महाकाल', 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' और 'ऑपरेशन दिव्य दृष्टि' ने अपराध की जड़ें हिलाईं

» नजूल जमीन प्रकरण बना था माफियाओं के खिलाफ बड़ा टर्निंग पॉइंट

» केंद्र ने भरोसा जताया अखिल कुमार बने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एमडी व सीईओ

आज दिनांक 07.10.25 को समय सायं 17:00 बजे पुलिस ऑफिस सभागार में नवनियुक्त पुलिस आयुक्त कानपुर नगर श्री रघुवीर लाल द्वारा पदभार ग्रहण किया जाएगा !

आईपीएस अखिल कुमार ने तोड़ा पुलिस-पत्रकार-वकील गठजोड़, हजारों लोगों को दिलाई बड़ी राहत

प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर शहर, जिसे कभी अपराधियों की शरणस्थली कहा जाता था, वहीं पर आईपीएस अखिल कुमार ने कानून का ऐसा अध्याय लिखा जिसने अपराध की जड़ों को हिला दिया। 4 जनवरी 2024 को जब उन्होंने पुलिस आयुक्त की कमान संभाली, तब शहर में अपराध, अवैध कब्ज़े और वसूली गिरोहों का जाल गहराई तक फैला था।लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि इरादा दृढ़ हो और नीयत साफ़, तो किसी भी व्यवस्था को बदला जा सकता है।

अखिल कुमार ने न केवल माफियाओं पर कार्रवाई की बल्कि उस अदृश्य गठजोड़ को भी तोड़ा जो वर्षों से पुलिस, पत्रकार और वकीलों के बीच पनप चुका था। यह गठजोड़ कानपुर की प्रशासनिक व्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उन्होंने बिना किसी दबाव के, केवल सबूतों के आधार पर कार्रवाई की और धीरे-धीरे पूरे शहर को राहत की सांस दिलाई।

कानपुर के सिविल लाइंस में एक हजार करोड़ रुपये की नजूल भूमि पर कब्ज़ा करने की कोशिश ने जब शहर में हलचल मचाई, तब पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने कानून की शक्ति का सही उदाहरण पेश किया।प्रभावशाली लोगों के दबावों को नज़रअंदाज़ करते हुए उन्होंने आरोपी अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार कराया और उसके 26 सदस्यीय गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई की।यह वह मोड़ था जब शहर ने पहली बार देखा कि अपराधी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं।कई नेताओं और अधिवक्ताओं ने अखिल कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्हें अहसास हुआ कि उनकी अपनी फाइलें भी खुल सकती हैं, विरोध स्वतः शांत हो गया।इसके बाद पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई का ऐसा दौर चला जिसने अपराध की पूरी श्रृंखला को तोड़कर रख दिया।

ऑपरेशन महाकाल अपराध के तंत्र पर महाघात

मार्च 2025 में गठित एसआईटी ने 'ऑपरेशन महाकाल' की शुरुआत की। इस अभियान ने उन गिरोहों की जड़ें उखाड़ दीं जो जमीन कब्जाने और होटल कारोबारियों से वसूली के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर झूठे मुकदमे दर्ज कराते थे।

इस नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके सहयोगी लवी मिश्रा को जेल भेजा गया।जांच के दौरान चार और नए मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें कई प्रभावशाली नामों का खुलासा हुआ।अखिल कुमार की सख्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दीनू उपाध्याय, अरिदमन सिंह, नारायण सिंह भदौरिया और दीपक जादौन जैसे नाम भी कानून के शिकंजे में आ गए।इसी तरह, कमलेश फाइटर गिरोह को भी पुलिस ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।'ऑपरेशन महाकाल' ने न केवल अपराधियों में भय पैदा किया बल्कि आम नागरिकों में कानपुर पुलिस के प्रति विश्वास भी जगाया।

तकनीक और निगरानी से जुड़ी नई सोच ऑपरेशन त्रिनेत्र और दिव्य दृष्टि

अखिल कुमार की कार्यशैली सिर्फ सख्ती तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने आधुनिक तकनीक के ज़रिए पुलिसिंग को नया चेहरा दिया।

'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत कानपुर के सभी थानाक्षेत्रों में हाई-क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, जिससे अपराध की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हुई।इसके अलावा 'ऑपरेशन दिव्य दृष्टि' के माध्यम से सभी हिस्ट्रीशीटर और जिलाबदर अपराधियों की ऑनलाइन निगरानी शुरू की गई, जिससे अपराध की पुनरावृत्ति पर नियंत्रण पाया जा सका।अखिल कुमार की सोच सिर्फ अपराध रोकने की नहीं, बल्कि अपराधियों को सुधारने की भी थी। 'मिशन हौसला' के तहत उन्होंने छोटे अपराधों में फंसे युवाओं को सुधार का मौका दिया उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़कर लोन दिलाया गया और स्वयं का रोजगार शुरू करने में मदद की गई।इस मानवीय पहल ने उन्हें एक संवेदनशील और दूरदर्शी अधिकारी के रूप में स्थापित किया।

जनता के दिलों में जगह शासन का विश्वास

कानपुर के लोग आज भी याद करते हैं कि अखिल कुमार के कार्यकाल में शहर ने वास्तविक बदलाव देखा।चाहे पुलिस की जवाबदेही हो या जनता की सुरक्षा, हर स्तर पर एक नई ऊर्जा दिखाई दी।

कानून व्यवस्था को सख्ती और संवेदनशीलता दोनों के साथ संभालने की उनकी कला ने राज्य ही नहीं, केंद्र सरकार का भी ध्यान खींचा।केंद्र ने उनके उत्कृष्ट कार्य को सम्मान देते हुए उन्हें डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह पद न केवल उनकी दक्षता का प्रमाण है, बल्कि यह दिखाता है कि ईमानदार और परिणाममुखी अफसर हमेशा आगे बढ़ते हैं।

जब एक दिन की एसीपी रिचा ने 84 साल के जयसिंह की सुनी पुकार!

बिल्हौर में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत छात्रा ने संभाली कार्यालय की कमान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। थाना बिल्हौर क्षेत्र के दादरपुर कटहा गांव के 84 वर्षीय जयसिंह उर्फ सिंह ने बताया कि उनके बेटे अवधेश ने लालचवश उनकी कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है और उन्हें व उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बेटे ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जयसिंह का कहना है कि उन्होंने अपनी चारों संतानों में जमीन बाँट दी थी, पर अपने और पत्नी के भरण-पोषण के लिए कुछ हिस्सा अपने पास रखा था, जिस पर अब बेटे ने जबरन कब्जा कर लिया है.

सोमवार को यह मामला तब सुर्खियों में आया जब महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत जीपीआरडी महाविद्यालय की एमएससी प्रथम वर्ष की छात्रा रिचा कटियार ने एक दिन की एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) बनकर बिल्हौर एसीपी कार्यालय का कार्यभार संभाला। रिचा ने फरियादी जयसिंह की व्यथा सुनी और बुजुर्ग दंपति को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने संबंधित थाने को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

» फरियादियों को दिलाया न्याय का भरोसा।

कार्यालय पहुंचने पर एसीपी अमरनाथ यादव और पुलिसकर्मियों ने रिचा का स्वागत किया। दिनभर उन्होंने कार्यालय में आने वाली महिलाओं और फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया।

रिचा कटियार ने कहा कि हर महिला और हर नागरिक को सुरक्षा का अधिकार है। हमें अन्याय सहने के बजाय आवाज़ उठानी चाहिए, तभी समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। इस मौके पर एसीपी अमरनाथ यादव ने मौजूद छात्राओं एवं महिलाओं को सुरक्षा से जुड़े सरकारी हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 1098, 1930, 108 और 181 की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि किसी भी संकट में महिलाएं इन नंबरों पर तुरंत मदद पा सकती हैं। बताया कि इस तरह के आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नारी,समृद्ध प्रदेश अभियान को आगे बढ़ाने का हिस्सा हैं। पुलिस विभाग का उद्देश्य महिलाओं को न केवल सुरक्षित बल्कि आत्मनिर्भर बनाना भी है। इस दौरान कस्बा इंचार्ज प्रेमवीर,अरौल इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव, महिला दरोगा समेत कई पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

बिल्हौर से किशोरी गायब, चंबलपुर के युवक-युवती पर अपहरण का शक

वैष्णो देवी दर्शन के बहाने बुलाकर घर से ले गए आरोपी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर कस्बे की एक नाबालिग लड़की रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई है। परिजनों ने मध्यप्रदेश में भिंड के चंबलपुर निवासी युवक-युवती पर बेटी को बहकाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की मां के मुताबिक करीब एक साल पहले चंबलपुर निवासी विकास राजावत पुत्र संदीप और उसकी बहन मोना उनके घर आए थे। इसी दौरान दोनों ने बेटी से जान-पहचान बढ़ाकर उसका भरोसा जीत लिया।

बीते 29 सितंबर को दोनों ने वैष्णो देवी मंदिर दर्शन का बहाना बनाकर किशोरी को फोन किया। मां के मना करने के बावजूद आरोपियों ने किसी तरह उसे बुला लिया। शाम करीब साढ़े सात बजे लड़की बिना बताए घर से निकल गई। जब परिजनों ने आरोपियों से फोन पर पूछताछ की तो अभद्रता करते हुए उन्होंने फोन काट दिया। लगातार खोजबीन के बावजूद जब कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई।

कोतवाल अशोक कुमार सरोज ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लड़की को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्लास में पढ़ाने के बजाय पोर्टल में उलझे गुरु जी!

सरकारी स्कूलों में 35 से अधिक ऐप-पोर्टल पर डेटा फीडिंग का बोझ

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति बच्चों को शिक्षित करने के लिए की थी, लेकिन अब हालात यह हैं कि उन्हें बाबूगीरी करनी पड़ रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इतने एप और पोर्टल लागू कर दिए हैं कि अब शिक्षक ब्लैकबोर्ड से ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप पर दिखते हैं।

जानकारी के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 35 से अधिक ऐप और ऑनलाइन पोर्टल संचालित हो रहे हैं। इन सभी में प्रतिदिन डाटा फीड करना, रिपोर्ट भेजना और अपडेट करना शिक्षकों की जिम्मेदारी बन गई है। इसके कारण शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कहीं दो शिक्षक हैं तो कहीं केवल एक, और उन पर शासन की योजनाओं, मीटिंगों, सीएम हेल्पलाइन, ओलंपियाड, मोगली महोत्सव, सेवा पखवाड़ा, गणवेश व साइकिल वितरण जैसी तमाम जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं।

दिनभर स्कूल में पहुंचने के बाद शिक्षक या तो रिपोर्ट बना रहे होते हैं या फिर किसी पोर्टल पर डाटा अपडेट कर रहे होते हैं।

यह है प्रमुख एप और पोर्टल

एम-शिक्षा मित्र, समग्र शिक्षा पोर्टल, पीएम पोषण, आरएसकेएमपी, एजुकेशन पोर्टल 2.0 व 3.0, हमारे शिक्षक, चाइल्ड ट्रैकर, पुस्तक वितरण, सार्थक, प्रशस्त, दीक्षा, शाला सिद्धि, विनोबा, स्विफ्ट चैट, यू-हाइस, ईको क्लब, एनपीएस, उमंग, सक्षम कार्यक्रम, विमर्श पोर्टल, स्क्वेयर पंडा, कर्मचारी एप आदि।

प्रत्येक पोर्टल पर अलग-अलग जानकारी समय पर अपलोड करनी होती है। ज़रा सी देरी हुई नहीं कि कार्यवाही की चेतावनी शिक्षक के सिर पर लटक जाती है।

प्राथमिक स्कूलों में आ रही सबसे अधिक दिक्कतें

जहां दो शिक्षक हैं, वहां एक को पोर्टल अपडेट में लगना ही पड़ता है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि वे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं बचता।

नीतियों ने बिगाड़ा हाल

शिक्षकों के अनुसार सरकार की इन नीतियों का नतीजा यह है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन लगातार घट रहा है। कई स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। हम शिक्षक हैं, बाबू नहीं- लेकिन हमें पढ़ाने की जगह कागज़ी काम में झोंक दिया गया है, यही कहना है हर एक शिक्षक का।

सम्पादकीय

सभ्य समाज के लिये शर्म की बात

बेटियों की साक्षरता में वृद्धि और कामकाजी क्षेत्र में लगातार उनकी बढ़ती भूमिका के बावजूद यदि दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि होती है, तो यह शर्मनाक स्थिति ही कही जाएगी। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की वह रिपोर्ट चौंकती है कि साल 2023 के दौरान देश में दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में 14 फीसदी मामले ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष के दौरान दहेज के कारण देशभर में 6,100 महिलाओं की मौत दर्ज की गई है। 21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहा जा रहा है और हम रूढ़िवादी सोलहवीं सदी में जी रहे हैं। लड़कियों के साथ यदि परिवार व्यवस्था में भेदभाव होता है और भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो उसके मूल में भी दहेज का अभिशाप ही है। लगातार खर्चीली होती उच्च शिक्षा व्यवस्था में बेटियों की शिक्षा पर बड़ा खर्च करने के बाद यदि मां-बाप को दहेज देना पड़ता है तो यह शर्मनाक स्थिति है। हालांकि, पिछले कुछ समय से पारिवारिक विवाद व अन्य कारकों को दहेज का मामला बनाने के कुछ मामले अदालतों की चिंता का भी विषय रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद समाज में दहेज के लिये उत्पीड़न की घटनाएं कटु सत्य है। यह भी एनसीआरबी की रिपोर्ट का यथार्थ है कि देश में हर रोज दहेज के लिये हत्याएं दर्ज हो रही हैं। बेटियों को पढ़ाने तथा सरकारों द्वारा उनके सशक्तीकरण के तमाम प्रयासों के बावजूद दहेज का दानव यदि अट्टहास कर रहा है तो यह हमारे समाज की असफलता ही कही जाएगी।

निस्संदेह, हमारे समाज में सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। एक समय नारा लगाया जाता था कि दुल्हन ही दहेज है। इस नारे को हकीकत बनाने की जरूरत है। कहीं न कहीं इस संकट के मूल में पितृसत्तात्मक सोच भी जिम्मेदार है। जिसमें स्त्रियों को वाजिब हक न देकर उन्हें कमतर आंका जाता है। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि दहेज प्रथा उन्मूलन के लिये सख्त कानून होने के बावजूद इस कुप्रथा पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। आखिर क्यों दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत मामले लगातार बढ़ रहे हैं। समाज में साक्षरता वृद्धि और जागरूकता अभियानों के बावजूद स्थिति जस की तस है। विडंबना यह है कि दहेज उत्पीड़न के ज्यादातर मामले बड़े हिंदी प्रदेशों में सामने आए हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और फिर बिहार दूसरे नंबर पर है। ये हजारों मामले समाज में स्त्रियों की विडंबनापूर्ण स्थिति को ही दर्शाते हैं। समाज में उपभोक्तावादी सोच के चलते भी दहेज की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। हमें विचार करना होगा कि समाज में दहेज के संकट की जड़ों पर कैसे प्रहार किया जाए। राष्ट्र का विकास तब तक एकांगी ही रहेगा, जब तक आधी दुनिया को समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता। दहेज के मामलों में न्याय भी शीघ्र देने की आवश्यकता है। आज जरूरत इस बात की है कि बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वे समाज में सम्मानजक ढंग से बिना किसी पर निर्भर रहकर जीवनयापन कर सकें।

राहुल के लिए घरेलू चुनौतियों पर ध्यान देना जरूरी

ज्योति मल्होत्रा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान अकसर सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करते रहे हैं जिस पर देश में सवाल उठते हैं। ऐसी बयानबाजी उन्होंने हाल ही में कोलंबिया से की। जबकि देश की सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी की बेहतरी के लिए जरूरी है कि वे प्रतिदिन संसद के अंदर और बाहर अपनी दलीलों को धारदार बनाने के लिए तैयार रहें।कोलंबिया के एनविगाडो से अपलोड की गई हालिया तसवीर में, राहुल गांधी ने अपनी पहचान का मार्का बनी सफ़ेद टी-शर्ट की जगह नेवी ब्लू शर्ट, पफ़र जैकेट और खाकी कार्गो पैंट पहन रखी है; पृष्ठभूमि में बजाज ऑटो निर्मित पल्सर बाइक है। एक्स पर डाली इस फोटो के साथ संलग्न कमेंट है–'कोलंबिया में बजाज, हीरो और टीवीएस को इतना अच्छा प्रदर्शन करते देख गर्व हो रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां दोस्तवाद से नहीं बल्कि नवाचार से जीत सकती हैं।'

लेकिन कांग्रेस पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता को ज़रूर पता होना चाहिए कि बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज के पिता राहुल बजाज– उदारीकरण से पहले युग में, लाइसेंस राज के दिनों में, जब भयानक लालफीताशाही से निबटने में सही लोगों तक पहुंच रखना ज़रूरी था– वे संरक्षणवाद के अग्रणी पैरोकार थे और उन्होंने आर्थिक सुधार के विचार के ख़िलाफ़ तगड़ी लड़ाई लड़ी थी। बड़े पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों का गुट,बॉम्बे क्लब, सीनियर बजाज जिसके एक सक्रिय सदस्य थे, उसका जोर अपने कामकाज में आमूल-चूल सुधार की बजाय सामाजिक-राजनीतिक संबंधों पर ज्यादा था, गलाकाट महत्वाकांक्षा में उलझने की बजाय भाईचारा निभाने का बीते वक्त का सुलभ रास्ता, तथापि था तो दोस्तवाद ही।राहुल की सोशल मीडिया टिप्पणी गौरतलब है कि वे कोलंबिया और ब्राज़ील सहित चार दक्षिण अमेरिकी देशों में से पहले देश की यात्रा पर हैं – हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं बताया कि शेष दो मुल्क कौन से हैं। बीते गुरुवार को उन्होंने एनविगाडो स्थित ईआईए विश्वविद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने भाजपा द्वारा 'भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमले' के बारे में बात की।इस टिप्पणी पर खूब आलोचना हुई कि कांग्रेस नेता विदेशी जमीं से सत्तारूढ़ पार्टी पर बार-बार हमला क्यों करते हैं, जिससे आगे ये प्रश्न उठते हैं:- क्या घरेलू राजनीति की आलोचना देश के भीतर तक ही सीमित रहनी चाहिए? क्या आंतरिक राजनीतिक लड़ाई को विदेशी धरती तक ले जाकर राहुल पूरी तरह गलत कर रहे हैं? और तीसरा, कुछ हद तक असंबंधित प्रश्न, यह कि राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका गए क्यों –ठीक वैसे ही जब कुछ महीने पहले मलेशिया, अप्रैल में बोस्टन, और साल की शुरुआत में दो बार वियतनाम भी गए?

यह लेख 2014 के बाद से राहुल की कथित 247 विदेश यात्राओं के बारे में नहीं है, जैसा कि भाजपा हमें यकीन दिलवाना चाहती है, जोकि सच नहीं है – निश्चित रूप से, कांग्रेस नेता को अपने विचार फैलाने, नई जगहों की यात्रा करने और नए लोगों को प्रभावित करने का हक है। हालांकि, अब समय आ गया है कि उस समस्या का सामाना करने का जो पिछले कुछ वर्षों से भारत के लोकतंत्र के दिल में कुलबुला रहा है – यानि सत्तारूढ़ भाजपा और भारत की सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी के बीच बढ़ती दरार। यह तनाव इस तथ्य से और बढ़ गया है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से, पिछले एक दशक में कांग्रेस चुनाव-दर-चुनाव हारती गई है। लेकिन क्योंकि यह अभी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी बनी हुई है –भले ही कुछ सूबों में भाजपा की बजाय कुछ अन्य दल सत्तारूढ़ हैं, चाहे यह डीएमके, टीएमसी, 'आप' या फिर वाम मोर्चा हो, लेकिन वे गिनती में नहीं हैं– और कांग्रेस पर ही भाजपा के अनवरत और भयानक प्रहारों का निशाना रही है। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनेता, जिन्होंने देश को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के पथ पर अग्रसर किया, निशाने पर हैं।पार्टी के सबसे ताकतवर व्यक्ति होने के नाते राहुल गांधी तो और भी आसान शिकार हैं, लेकिन उन्हें वह करना मंजूर नहीं कि नेता को कीलों वाली कुर्सी पर बैठना या कांटों का ताज पहनना पड़ता है।

विकास की कीमत पर मुफ्त की रेवड़ियां

बिहार में वादों की बहार

ज्वाला सिंह दास

ये योजनाएं अल्पकालिक रूप से मतदाताओं को आकर्षित करने में कारगर हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा दे सकती हैं और बुनियादी ढांचे तथा विकास परियोजनाओं को पीछे धकेल सकती हैं।भारत की राजनीति में चुनावी मौसम आते ही मुफ्त सुविधाओं और लोकलुभावन वादों की बौछार शुरू हो जाती है, जिन्हें आलोचक अक्सर 'रेवड़ियां' कहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इसी क्रम में कई योजनाओं की घोषणा की है–जिनमें महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता, बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपये की एकमुश्त राशि, मुफ्त बिजली, पेंशन में दो गुना वृद्धि और निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की सहायता राशि शामिल हैं।इन योजनाओं पर अगले दो वर्षों में 2,800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है, जबकि बिहार का वार्षिक राजस्व लगभग 56,000 करोड़ रुपये है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस तरह की लोकलुभावन घोषणाएं राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर बोझ बनेंगी, या यह सामाजिक कल्याण की दिशा में एक जरूरी कदम हैं?बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस) के बीच कांटे की टक्कर है। नीतीश सरकार ने महिलाओं (51 प्रतिशत मतदाता) और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। 18 सितंबर को शुरू हुई 10,000 रुपये की सहायता योजना 12 लाख युवाओं तक पहुंचेगी। इसके अलावा, 1.67 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण जैसे वादे हैं। दूसरी ओर, आरजेडी ने जातिगत सर्वे के आधार पर और अधिक कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया है।उधर, सामाजिक मंचों पर कुछ लोग इन घोषणाओं को

'वोट खरीदने की रणनीति' मानते हैं, जबकि कुछ इसे 'सामाजिक कल्याण' की दिशा में एक कदम मानते हैं। इन योजनाओं का फोकस विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और अति पिछड़ा वर्ग जैसे समुदायों पर है, जिससे राज्य की जाति-आधारित राजनीति को और गति मिलने की संभावना है।

हालांकि, ये योजनाएं अल्पकालिक रूप से मतदाताओं को आकर्षित करने में कारगर हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा दे सकती हैं और बुनियादी ढांचे तथा विकास परियोजनाओं को पीछे धकेल सकती हैं। विपक्षी दल भी अब इसी राह पर चलने लगे हैं, जिससे राज्य की राजनीति में एक तरह का 'रेवड़ी युद्ध' शुरू हो गया है—जहां नीतियों की प्रतिस्पर्धा की जगह वादों की होड़ ने ले ली है।बिहार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। इस समय प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 40 प्रतिशत कम है और बेरोजगारी दर 7.2 प्रतिशत के आसपास है। इन योजनाओं से राज्य के खजाने पर शुरुआत में 2,800 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यदि योजनाएं स्थायी हुईं, तो कर्ज-जीएसडीपी अनुपात (वर्तमान में 36 प्रतिशत) और बढ़ेगा। उधर, मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं बिजली बोर्डों पर दबाव डालेंगी, जो पहले से घाटे में चल रहे हैं। मुफ्त बिजली से पानी और ऊर्जा का दुरुपयोग बढ़ेगा, और नकद सहायता से कार्यबल की भागीदारी कम हो सकती है। कृषि-आधारित बिहार में, जहां 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है, संसाधनों का असंतुलित आवंटन दीर्घकालिक विकास के लिए गंभीर बाधा बन सकता है। पहले से ही सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचों पर खर्च सीमित है; 'रेवड़ियों' पर बढ़ता खर्च इन जरूरी क्षेत्रों की उपेक्षा को और बढ़ा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में रेवड़ियों को 'लोकतंत्र के लिए खतरा' बताया था और विशेषज्ञ समिति बनाने का सुझाव दिया था। फिर भी, दल विकास के बजाय अल्पकालिक लाभ पर जोर दे रहे हैं। यह प्रवृत्ति जातिगत और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। बिहार में ओबीसी और दलित केंद्रित योजनाएं अन्य राज्यों में भी ऐसी ही मांगें बढ़ाएंगी। इससे राष्ट्रीय राजनीति में 'वोट के लिए मुफ्त' की संस्कृति गहरी होगी।भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेवड़ियों का बोझ बढ़ रहा है।

कैचवर्ड – मुसीबत की डगर

विकास के दावे हुए हवा-हवाई, दलदल बनी सड़क

» मन्नूलाल कॉलेज से बेला मार्ग तक सड़क पर जलभराव, छात्रों और ग्रामीणों की बढ़ी मुसीबत

» योगी सरकार के आदेश के बावजूद मरम्मत अधर मे लटकीं, दीपावली तक सुधार होने पर संदेह

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक चौबेपुर अंतर्गत आने वाली मन्नूलाल डिग्री कॉलेज से बनसठी बेला मार्ग की डामर सड़क अब पूरी तरह जर्जर और खतरनाक हो चुकी है। जगह-जगह गड्ढों ने सड़क का स्वरूप मिटा दिया है। बरसात होने की वजह से सड़क पर मिनी तालाब बन गए हैं। यह मुख्य मार्ग

प्रतिदिन हजारों लोगों की आवाजाही का रास्ता है, इसके बावजूद अब तक किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि की नजर इस तरफ नहीं पड़ी है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सड़क से प्रतिदिन मन्नूलाल कन्या विद्यालय के सैकड़ों छात्र–छात्राएं गुजरती हैं।

सड़क की हालत इतनी खराब है कि किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रीय नागरिकों को भी आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद अभी तक मरम्मत का कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश की सभी सड़कों को दीपावली तक दुरुस्त कराने के निर्देश दिए थे,

लेकिन चौबेपुर क्षेत्र की यह सड़क उन आदेशों को ठेंगा दिखा रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बिल्हौर विधायक और संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस

समस्या की जानकारी होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या यह सड़क दीपावली से पहले ठीक होती है या फिर लोगों को सरकारी दावों और दलदली मार्ग के बीच फंस कर ही निकलना पड़ेगा।

टूटा घर फिर जुड़ा, छह माह बाद साथ-साथ लौटे पति-पत्नी

» घरेलू विवाद में अलग रह रहे रितू और अमित सोनकर की काउंसलिंग कर पुलिस ने बचाया रिश्ता

» थाना काकादेव में एक माह 5 दिन में 12वां पति–पत्नी के बीच हुए विवाद का मामला सुलझाया गया

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर नगर। थाना काकादेव में शुक्रवार को एक और बिखरता हुआ घर फिर से बस गया। जयप्रकाश नगर निवासी प्रीतु सोनकर ने परिवार परामर्श केंद्र में शिकायत दी थी कि उनके पति अमित सोनकर ने घरेलू विवाद के चलते उनसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है।

वह पिछले छह महीने से मायके में रह रही थीं। शिकायत की जानकारी पर सहायक पुलिस आयुक्त स्वरूप नगर और थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर परिवार परामर्श कमेटी प्रभारी वरिष्ठ उपनिरीक्षक शिवकरन वर्मा व काउंसलर शगुन खट्टर और श्रीमती कंचन सिंह ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग की। काउंसलिंग के दौरान दोनों को समझाया गया कि झगड़ों और आरोप–प्रत्यारोप से न केवल परिवार का विकास रुकता है, बल्कि जीवन भी बर्बाद हो जाता है। गहन बातचीत और समझाने के बाद प्रीतु और अमित सोनकर ने भविष्य में किसी तरह का विवाद न करने की शपथ लेते हुए फिर से साथ रहने का निर्णय लिया। काकादेव थाना क्षेत्र में यह बीते एक माह 5 दिन में 12वां पति–पत्नी विवाद है जो समझौते के जरिए सुलझाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिवार परामर्श कमेटी के निरंतर प्रयासों से कई टूटते रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं और लोगों में इस पहल के प्रति भरोसा बढ़ रहा है।

कानपुर के 17 वर्षीय रूद्राक्ष ने रचा इतिहास

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में कानपुर का नाम एक बार फिर देशभर में रोशन हुआ है। सर पदमपत सिंघानिया शिक्षा केंद्र, कानपुर के कक्षा 12 के छात्र रूद्राक्ष ने ड्रोन उड़ान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है।17 वर्षीय रूद्राक्ष ने

» ड्रोन उड़ान में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड!

» रूद्राक्ष के पिता डॉ. आरके. निरंजन, मूल रूप से उरई जालौन निवासी हैं जो कि वर्तमान में कानपुर नगर निगम में सीवीओ के पद पर हैं

स्वयं द्वारा तैयार किए गए दृष्टि नियंत्रित (पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण वाले) ड्रोन को 7.266 किलोमीटर की दूरी तक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाकर यह अद्भुत कीर्तिमान बनाया। उनकी इस अनूठी उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 28 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की जा रही है।

संस्था की ओर से रूद्राक्ष को प्रमाणपत्र, सम्मान पत्र और उपलब्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रूद्राक्ष के पिता डॉ. आर. के. निरंजन, मूल रूप से उरई जालौन निवासी जो कि वर्तमान में कानपुर नगर निगम में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, ने अपने पुत्र की इस सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि 卐रूद्राक्ष ने कम उम्र में जिस तरह तकनीकी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई है, वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है।卐

विद्यालय की प्रधानाचार्या भावना गुप्ता ने भी रूद्राक्ष को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल विद्यालय बल्कि पूरे शहर के लिए गर्व का विषय है।

रूद्राक्ष इससे पहले भी विभिन्न आकारों और क्षमताओं वाले कई ड्रोन स्वयं बनाकर सफलतापूर्वक उड़ा चुके हैं। तकनीक के प्रति उनकी लगन और नवाचार के प्रति जिज्ञासा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है।

रूद्राक्ष का यह रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि समर्पण, मेहनत और जिज्ञासा के बल पर युवा पीढ़ी देश का नाम विश्व पटल पर ऊँचा उठा सकती है। 卐रूद्राक्ष ने साबित किया है कि उम्र नहीं, जुनून और नवाचार ही सफलता की असली पहचान है।

अयोध्या की गूंज: क्या रामनगरी से उठेगी दलित प्रतिनिधित्व की आवाज?

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

अयोध्या।उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जातीय समीकरणों का तिलिस्म गहराने लगा है। अयोध्या के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव व फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने साफ कहा समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, पार्टी जिताऊ नेताओं पर दांव लगाएगी।

लेकिन यह बयान जितना सीधा दिखता है, उतना है नहीं। क्योंकि जब यही अवधेश प्रसाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके समर्थक नारा लगा रहे थे मथुरा ना काशी, अबकी बार अवधेश पासी।

यह नारा न सिर्फ जातीय पहचान का प्रतीक था बल्कि एक समुदाय विशेष को गोलबंद करने की रणनीति का हिस्सा भी।

-वोट चोरी नहीं, डकैती – सपा सांसद का हमला

अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश में वोट चोरी की नहीं, डकैती की सरकार चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा, तो मिल्कीपुर उपचुनाव का जिक्र एक डकैती के रूप में दर्ज होगा। हालांकि जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि अगर वोट चोरी होती तो आप सांसद कैसे बने? तो सांसद चुप्पी साध गए।

यह चुप्पी बहुत कुछ कह गई शायद सपा भी जानती है कि उसके राजनीतिक तीर अब जातीय भावनाओं और सरकार विरोधी लहर के बीच ही चल सकते हैं।

अवधेश प्रसाद का बयान आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति की ओर इशारा करता है। लोकसभा की तरह अयोध्या विधानसभा सीट पर भी सपा दलित प्रत्याशी उतार सकती है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा ने पासी समाज को ध्यान में रखकर ही अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया था। अब अटकलें हैं कि अयोध्या की सामान्य सीट पर भी दलित उम्मीदवार उतारने की योजना पर अखिलेश यादव गंभीर हैं।एक समय था जब पासी समुदाय बसपा की रीढ़ हुआ करता था।

मायावती के शासनकाल में यह समाज जाटवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा दलित वोटबैंक था।

लेकिन समय के साथ पासी नेताओं का बसपा से मोहभंग हुआ और यह वोट बैंक पहले भाजपा, फिर अब सपा की ओर झुकने लगा।

रामनगरी अयोध्या की माटी में जब मर्यादा पुरुषोत्तम की सीख बसती है, तो फिर यहाँ लोकतंत्र में 'मर्यादा' क्यों गुम है? क्या इस पावन नगरी से कभी कोई वाल्मीकि, कोई दलित चेहरा विधानसभा में जनप्रतिनिधि बनकर आवाज़ बुलंद कर पाएगा? या फिर अयोध्या हमेशा सत्ता के प्रतीक बनाम पीड़ित के प्रतीक के बीच झूलती रहेगी?

– ओमप्रकाश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार
(प्रेस क्लब अयोध्या में 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम के दौरान)

उत्तर प्रदेश में पासी समाज की हिस्सेदारी लगभग 4त्न है,

लेकिन अवध और पूर्वांचल में यह संख्या 16प्रति तक पहुंचती है।

अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ इन जिलों में पासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर सपा की जीत में अवधेश प्रसाद की जातीय पहचान एक बड़ा फैक्टर रही। अब वही रणनीति विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जा सकती है। सपा की नई राजनीतिपिछड़ा–दलित–अल्पसंख्यक की अवधारणा पर टिकी है।परंतु अब लगता है कि अखिलेश यादव सवर्ण वोटों को भी साधने की कोशिश में हैं। अवधेश प्रसाद का जाति नहीं, जिताऊ बयान इसी रणनीति का हिस्सा है एक ओर दलित चेहरे को आगे रखना और दूसरी ओर सवर्ण वर्ग को संदेश देना कि पार्टी किसी एक जाति की बंदिश में नहीं बंधी।1993 के बाद से अयोध्या विधानसभा सीट पर सपा को सिर्फ एक बार सफलता मिली ।2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने यहां रोड शो कर चुनावी माहौल बनाया था, लेकिन मतदान के पूर्व की रात विपक्ष की रणनीति ने सब पर पानी फेर दिया। अब 2027 की लड़ाई के लिए सपा फिर से वही अयोध्या प्रयोग दोहराने की तैयारी में है।अवधेश प्रसाद के सवाल फ्क्या कोई वाल्मीकि अयोध्या का प्रतिनिधित्व कर पाएगा? सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा का संकेत है। राम की नगरी में अब राजनीति धर्म बनाम जाति नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व बनाम प्रतीक की लड़ाई बनने जा रही है।और इस बार सपा, भाजपा, बसपा सबके लिए सवाल एक ही है अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर किसकी राजनीतिक मर्यादा टिकेगी?

बेसिक शिक्षा:अब शिक्षक व विद्यार्थियों की लगेगी डिजिटल हाजिरी

» बेसिक शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने जारी किया फरमान

परिषदीय स्कूलों में बच्चों की हर दिन लगेगी डिजिटल अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस को सीएम डैशबोर्ड पर एक नए प्रोजेक्ट के रूप में जोड़ा गया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे 1.50 करोड़ से ज्यादा बच्चों की अब रोजाना डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। स्टूडेंट अटेंडेंस को सीएम डैशबोर्ड पर एक नए प्रोजेक्ट के रूप में जोड़ा गया है। अक्तूबर के डाटा के आधार पर नवंबर से इसकी समीक्षा शुरू होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इस संबंध में सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत निर्देश भेजे हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि सीएम डैशबोर्ड पर बेसिक शिक्षा विभाग का नया प्रोजेक्ट स्टूडेंट अटेंडेंस को एकीकृत किया गया है।

विद्यालयों में उपस्थित छात्रों की संख्या मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर नवंबर से (अक्तूबर के डाटा के आधार पर) दिखेगी। आदेश के मुताबिक स्टूडेंट अटेंडेंस प्रोजेक्ट अक्तूबर से जिलों की रैंकिंग निर्धारण में भी शामिल किया जाएगा इसलिए सभी जिले आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें ताकि डाटा फीडिंग और अपडेशन में देरी न हो। सभी विद्यालयों से छात्र उपस्थिति का दैनिक अद्यतन (डेली अपडेट) उपलब्ध कराया जाएगा।

पिछले साल हुआ था विरोध–

बेसिक शिक्षा विभाग ने टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों में प्रयोग होने वाली 12 पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन की कवायद पिछले साल नए सत्र की शुरुआत के साथ की थी।

इसके लिए विद्यालयों में दो–दो टैबलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें शिक्षकों की भी डिजिटल उपस्थिति जुड़ी होने से प्रदेश भर में इसका काफी विरोध हुआ था। इसके बाद उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप पर इसे स्थगित कर दिया था। अभी मध्याह्न भोजन समेत कुछ ही पंजिका डिजिटलाइज हुई हैं।

जिला प्रशासन बढ़ाएगा सख्ती–

स्टूडेंट अटेंडेंस सीएम डैशबोर्ड से जुड़ने के बाद अब इसे लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के साथ

जिला प्रशासन भी सख्ती बढ़ाएगा क्योंकि सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। समीक्षा में स्थिति खराब होने पर जिला प्रशासन को भी जिम्मेदार माना जाएगा।

20 को मनाई जाएगी दीपावली, तिथियों को लेकर कोई संशय नहीं

» कुछ पंचांगों में तिथि की गड़बड़ी से बनी असंजस की स्थिति, काशी विद्वत परिषद ने दूर किया भ्रम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर। सनातन परंपरा में प्रकाश के महापर्व दीपावली का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। धन की देवी मां लक्ष्मी और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजा से जुड़ा यह पावन पर्व 20 या फिर 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं कुछ लोग दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच होने वाले एक दिन के गैप को लेकर परेशान है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की सभी सही तारीख को लेकर जो कन्फ्यूजन आपके मन में है, उसे काशी विद्वत परिषद ने दूर करते हुए एक मत से सही तारीखें घोषित कर दी हैं. आइए दिवाली समेत सभी पर्वों की सही तारीखें ज्योतिष एवं शास्त्रीय नियमों के आधार पर जानते हैं।

काशी विद्वत परिषद ने दूर किया कन्फ्यूजन

काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री प्रो. राम नारायण द्विवेदी के अनुसार सूर्य सिद्धांत के अनुसार ही पंचांग निर्माण की हमारी ऋषि परंपरा रही है। धर्म शास्त्र के अनुसार ही हमारे निर्णय पूर्णत– फलित होते हैं। इसी को आधार मानते हुए देखें तो 20 अक्टूबर को दोपहर 02–45 मिनट पर अमावस्या लग रही है। हमारे यहां प्रदोष व्यापिनी अमावस्या ही दीपावली पर ग्राह्य होती है जो कि अगले दिन 04–15 बजे तक रहेगी। ऐसे में धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा।

एकमत होकर पर्वों पर निर्णय करेंगे

प्रो. राम नारायण द्विवेदी के अनुसार कुछ पंचांग में भ्रमवश दिखाया गया है कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या 21 अक्टूबर 2025 तक जा रही है जो कि गणितीय दृष्टि से देखें तो कहीं से भी संभव नहीं हो रहा है। उन पंचांगकारों से विमर्श करने के बाद तय हुआ है कि 2026 से हम एकमत होकर पर्वों पर निर्णय करेंगे। ताकि सनातनी परंपरा में पर्व की तिथि को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय न रहे।

20 को दोपहर 02:45 बजे से अमावस्या

20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 02–45 मिनट पर अमावस्या लग रही है। जो कि अगले दिन प्रात– 04–15 बजे तक रहेगी. ऐसे में धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा.

लापरवाही ने ले ली जान

लिफ्ट में फंसी गर्दन, श्रमिक की दर्दनाक मौत से फैक्ट्री में मचा हड़कंप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रायपुर चौराहे पर मंगलवार की सुबह एक बिस्किट फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया। कानपुर नगर निवासी हर्ष श्याम दासानी की ओम राज फूड्स प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में कार्यरत निखिल मिश्रा (26 वर्ष), पुत्र गिरीश बाबू निवासी अटा, थाना फफूंद, जनपद औरैया, की लिफ्ट में गर्दन फंस जाने से मौके पर ही मौत हो गई।हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और उत्पादन कार्य तत्काल रोक दिया गया।

सूचना पाकर पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची तथा घटना से जुड़े आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।मृतक निखिल मिश्रा फैक्ट्री परिसर में ही रहता था और मैदा की बोरियां लिफ्ट से ऊपर चढ़ाने का काम करता था। सुबह करीब आठ बजे कार्य के दौरान उसकी गर्दन लिफ्ट में फंस गई, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई।

सूचना मिलते ही एसडीएम सदर नीलिमा यादव, एएसपी राजेश पांडेय, सीओ सदर संजय वर्मा, इंस्पेक्टर रनियां शिवनारायण

» ओम राज फूड्स प्रोडक्ट्स में काम करते समय हुआ हादसा, जांच में जुटी पुलिस

» पांच घंटे बाद कटर से काटकर निकाला गया शव, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

सिंह व फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचे।एएसपी राजेश पांडेय ने बताया कि यह कार्य के दौरान हुआ हादसा है, मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। करीब पांच घंटे तक शव लिफ्ट में फंसा रहा। पुलिस और फैक्ट्री कर्मियों ने काफी प्रयास किया

मृतक की फाइल फोटो

लेकिन सफलता न मिलने पर कटर से लोहे की प्लेट काटकर दोपहर करीब एक बजे शव को बाहर निकाला गया।

बदहवास पिता

परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था

निखिल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। पिता किसान हैं और पीछे मां गीता देवी तथा दो छोटी बहनें हेमा और प्रिया हैं। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

ब्लॉक सरवनखेड़ा में हुआ भव्य रामायण पाठ एवं संकीर्तन

धार्मिक वातावरण में गूंजे राम के जयकारे, भक्तिमय हुआ पूरा परिसर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात (माती)।विकास खंड सरवनखेड़ा में आज एक दिवसीय रामायण पाठ एवं भव्य संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बाला जी संकीर्तन पार्टी, सरवनखेड़ा द्वारा किया गया,

जिसमें क्षेत्रभर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे।रामायण पाठ के पश्चात भजन–कीर्तन की मधुर धुनों पर पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने राम के जयकारों से पूरा परिसर गुंजा दिया।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक/खण्ड विकास अधिकारी बीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ एडीओ (आईएसबी) विमल सचान, लेखाकार संजय कुमार वर्मा, सुधीर अवस्थी, अनिल कटियार, श्यामसुन्दर, सुधीर कटियार, संतोष पाल, प्रदीप शुक्ला, दीपक यादव, मनोज द्विवेदी, संघमित्रा, जयकिशन, निर्मल एवं अंकित प्रियदर्शी सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।कार्यक्रम के अंत में क्षेत्र की सुख–समृद्धि एवं शांति की कामना के साथ सामूहिक आरती की गई। आयोजकों ने सभी अतिथियों और श्रद्धालुओं का धन्यवाद ज्ञापित किया।रामायण पाठ जैसे आयोजन समाज में धार्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों को सशक्त करते हैं। — बीरेंद्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी

मलासा में बंदरों का आतंक, बच्चों और महिलाओं पर लगातार कर रहे हमले

» घर की छतों और गलियों में घूम रहे हिंसक बंदर, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

» वन विभाग की लापरवाही पर लोगों में रोष, प्रशासन से जल्द समाधान की मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील के अंतर्गत ब्लॉक मलासा के मलासा गांव में इन दिनों बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक पर बंदरों के हमले हो रहे हैं। गांव में बंदरों के झुंड छतों और गलियों में दौड़ते रहते हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बंदर अब घरों में घुसकर सामान तोड़ रहे हैं और छतों पर सूखते कपड़े तक उठा ले जा रहे हैं। भगाने पर वे लखेद लेते हैं और कई बार हमला भी कर देते हैं। बंदरों के बढ़ते आतंक के कारण बच्चे अब घरों के बाहर खेलने से डरने लगे हैं, जबकि महिलाएं छतों पर काम करने से कतरा रही हैं। गांव के प्रधान प्रतिनिधि रवि सिंह ने बताया कि बंदरों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। गांव के निवासी लाला सिंह, गजेन्द्र सिंह, प्रदीप सिंह, बृजेंद्र उर्फ बऊआ, बटृन सिंह और मालिक सिंह ने बताया कि गांव में पिछले कई सालों से बंदर पकडने् का कोई अभियान नहीं चलाया गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और वन विभाग से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है ताकि गांव में बंदरों का आतंक खत्म हो सके।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

स्वराज इंडिया की खबर का असर

बेवजह लाठीचार्ज करने में एसपी ने तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात।भोगनीपुर थाना क्षेत्र के कुसरजापुर गांव में पानी को लेकर हुए विवाद और कथित लाठीचार्ज की खबर प्रकाशित होने के बाद स्वराज इंडिया की रिपोर्ट का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। हालांकि, लाठीचार्ज का आदेश देने वाले भोगनीपुर कोतवाल अमरेंद्र सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

घटना बीते रविवार की रात की है, जब दलित समाज के लोग गांव में खराब पड़ी पानी की टंकी के चलते एक सरकारी हैंडपंप से पानी भरने गए थे। यह हैंडपंप दूसरे समुदाय के व्यक्ति की बाउंड्री के

» भोगनीपुर लाठीचार्ज मामले में एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने लिया संज्ञान

» कोतवाल पर कार्रवाई न होने से उठे सवाल, वायरल वीडियो में दिखी पुलिस की बर्बरता

अंदर स्थित था।

इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने, गांव वालों के अनुसार, स्थिति को समझने के बजाय लाठीचार्ज शुरू कर दिया,

जिससे दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए।हालात बिगड़ने पर सीओ भोगनीपुर संजय सिंह व एसडीएम देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और देर रात तक गांव में स्थिति

स्वराज इंडिया

कानपुर देहात

पानी के विवाद को लेकर पुलिस ने बरसाई लाठियां, गांव में हुआ बवाल

सामान्य कराने की कोशिश की।

अधिकारियों ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा।

हैंडपंप कब्जा मुक्त कराने के निर्देश

घटना के बाद प्रशासन ने अब गांव के हैंडपंपों को कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार सुबह नायब तहसीलदार सूर्य प्रकाश व नगर पालिका ईओ अजय कुमार कुसरजापुर पहुंचे और लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि जहां-जहां सरकारी हैंडपंप निजी बाउंड्री के भीतर हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाएगा। संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने और कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में सरकारी संपति पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और गांव के हर व्यक्ति को पानी की समान सुविधा मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर प्रो. एच एन मिश्रा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुए शिक्षक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दीप्ती कटियार को विश्व शिक्षक दिवस पर पूर्व कुलपति प्रो. एच एन मिश्रा उत्कृष्ट शिक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया। दीप्ती कटियार कानपुर देहात जनपद के सरवनखेड़ा विकासखंड में स्थित प्राथमिक विद्यालय निनायाँ प्रथम में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें यह सम्मान रविवार को प्रो. एच एन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं इंटरनेशनल सेंटर इंग्लिश स्कूल के संयुक्त बैनर तले आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण व नवाचार की प्रशंसा की गई। उक्त समारोह में देश भर के 160 शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। शिक्षिका दीप्ती कटियार ने कहा कि यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि उन समर्पित शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देने में निरंतर लगे हैं। समारोह में विद्यालय की अध्यक्ष सुष्मित मिश्रा, मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी, विधायक क्रमश- नीलिमा कटियार, महेश त्रिवेदी, अभिजीत सिंह सांगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, अनिल दीक्षित, नीतू सिंह, डॉ. उमेश पालीवाल, नरेंद्र शर्मा, अनूप सिंह शैलेंद्र द्विवेदी, सुमालिका प्रभात, डॉ. मनोज कुमार प्रजापति सहित अनेक लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन नीरज कुमार चौधरी व साफिया रशीद ने किया। विद्यालय की निदेशिका मृदु चौहान, संयोजक डॉ. संदीप कुमार श्रीवास ने सभी का आभार जताया।

एसपी ने किया औचक निरीक्षण, वन स्टॉप सेंटर में महिला सुरक्षा पर खास फोकस

» सुविधाओं, साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता का किया गया गहन परीक्षण

» महिला सुरक्षा, गोपनीयता और स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने जिला अस्पताल अकबरपुर परिसर स्थित वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता और महिला पीड़िताओं के रहने की व्यवस्था का बारीकी से मूल्यांकन किया। उन्होंने पीने के पानी, वेंटिलेशन, सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड रखरखाव की भी जांच की। एसपी श्रद्धा पांडेय ने केंद्र में तैनात परामर्शदाताओं, सहायिकाओं और कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने रसोईघर में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, रसोई की स्वच्छता और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता की जांच की।

निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि आपातकालीन सहायता प्रणाली और शिकायत निस्तारण प्रक्रिया प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

निरीक्षण के उपरांत पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक कमरे, रसोईघर और शौचालय की दैनिक सफाई सुनिश्चित की जाए और पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक व सहानुभूतिपूर्ण माहौल प्रदान किया जाए।

उन्होंने रात्रि सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और महिलाओं की गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। एसपी ने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन देना है।

27 प्रतिशत आरक्षण- 'महासंग्राम' की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश

»मोहन यादव की जातिगत राजनीति से मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में सवर्ण समाज में गहराया आक्रोश

कई जगह चल रहे विरोध प्रदर्शन, भाजपा को हो सकता है नुकसान

» स्वराज इंडिया न्यूज

ब्यूरो भोपाल। मध्यप्रदेश की सियासत इन दिनों एक बार फिर जातिगत आरक्षण की आग में झुलस रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 14ल से बढ़ाकर 27ल करने की कोशिश ने पूरे राज्य में सवर्ण समाज और युवा वर्ग के बीच गहरा असंतोष पैदा कर दिया है।

जहाँ सरकार इसे सामाजिक न्याय का कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और सवर्ण संगठन इसे योग्यता पर हमला और जातिगत ध्रुवीकरण की साजिश करार दे रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से इस मामले की रोज़ाना सुनवाई होगी।अगर अदालत ने 27प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी, तो यह देशभर के लिए नया उदाहरण बन जाएगा।लेकिन अगर इसे असंवैधानिक माना गया, तो सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

सवर्ण समाज में उठी आवाज़ अब केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतावनी बन चुकी है।भाजपा के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह सामाजिक न्याय और योग्यता आधारित अवसर के बीच संतुलन कैसे बनाए।

राज्य की राजनीति अब सिर्फ आरक्षण के इर्द-गिर्द नहीं घूम रही — बल्कि यह नए सामाजिक समीकरणों की जंग का संकेत है।

73प्रति आरक्षण की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

मोहन यादव सरकार ने हाल ही में राज्य सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को 27ल तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है।

यदि यह लागू होता है, तो मध्यप्रदेश में कुल आरक्षण सीमा 73प्रति तक पहुँच जाएगी — जिसमें अनुसूचित जाति को 16प्रति, अनुसूचित जनजाति को 20प्रति, ओबीसी को 27प्रति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10प्रति आरक्षण मिलेगा। यह आंकड़ा सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की 50ल आरक्षण सीमा को पार करता है, जो 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस (मंडल कमीशन) में तय की गई थी।

इसी आधार पर इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी गई है, और अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी नियमित सुनवाई 8 अक्टूबर से शुरू हो रही है।

कानूनी दलीलें और विवादित रिपोर्ट

राज्य सरकार का कहना है कि मध्यप्रदेश की ओबीसी आबादी करीब 48-50ल है, जबकि सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसलिए, विशेष परिस्थितियों में 50प्रति की सीमा पार करना न्यायोचित है।

हालांकि, सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए दस्तावेजों में महाजन आयोग (1983) की रिपोर्ट और कुछ पुराने शोध दस्तावेज शामिल किए गए हैं, जिनमें धर्मग्रंथों से लिए गए अंशों को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

कई संगठनों ने आरोप लगाया कि इन दस्तावेजों ं हिंदू समाज को नीचा दिखाने वाले उद्धरण शामिल हैं।

सरकार ने सफाई दी कि ये उद्धरण नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक संदर्भों के रूप मंे संलग्न किए गए थे।

सवर्ण समाज का फूटा गुस्सा

राज्य के कई जिलों में सवर्ण समाज और युवा संगठनों ने योग्यता का सम्मान चाहिए, आरक्षण मध्यप्रदेश नहीं जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शन किए।

भोपल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा, जिसे सवर्ण समाज ने दशकों तक समर्थन दिया, अब उन्हीं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।

स्वर्ण युवा मंच और ब्राह्मण महासभा जैसे संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार आरक्षण वृद्धि को वापस नहीं लेती, तो राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। यह निर्णय सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि योग्यता की हत्या है। मेहनती युवा केवल जाति के नाम पर पीछे नहीं रह सकता,

— **अनिल मिश्रा, संयोजक, स्वर्ण युवा मंच (भोपाल)।**

कांग्रेस ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अदालत में कुछ और कहती है, और जनता के सामने कुछ और।वहीं समाजवादी और बहुजन संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सामाजिक प्रतिनिधित्व ही असली समानता है। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने बयान दिया है कि मोहन यादव सरकार सबको साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। ओबीसी को न्याय देना किसी के हक़ में कटौती नहीं है। कोर्ट में सच्चाई सामने आ जाएगी।

बेरोज़गारी और आरक्षण का टकराव

राज्य में बेरोज़गारी दर लगातार बढ़ रही है — CMIE के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2025 में मध्यप्रदेश की बेरोज़गारी दर 9.4ल तक पहुँच गई।

ऐसे में, युवाओं का गुस्सा आरक्षण को लेकर और भी उग्र हो रहा है।

कई छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या में जातिगत आधार पर आरक्षण का अनुपात बढ़ाने से मेहनती उम्मीदवारों के अवसर घटते जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (1992) में यह स्पष्ट किया था कि आरक्षण की सीमा 50ल से अधिक नहीं हो सकती, जब तक कोई असाधारण परिस्थितिफ न हो।तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इससे ऊपर आरक्षण को लेकर पहले भी कानूनी टकराव हुए हैं।अब मध्यप्रदेश का मामला इस पूरे देश में आरक्षण नीति की दिशा तय करने वाला मुकदमा बन सकता है।

महिलाओं ने दौड़ लगाकर दिया सशक्तिकरण का संदेश

मिशन शक्ति फेज-5 के तहत वॉक फॉर एम्पावरमेंट में उमड़ा उत्साह

»स्वराज इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद।मिशन शक्ति के पांचवे चरण के तहत महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से रविवार को फ्वॉक फॉर एम्पावरमेंट दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस आयुक्त जे. रविन्द्र गौड एवं अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया।

यह आयोजन कमिश्नरेट गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन जोन में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों, छात्राओं और सामाजिक संस्थाओं की महिलाओं ने भाग लिया। सभी प्रतिभागी हाथों में मिशन शक्ति के बैनर और महिला हेल्पलाइन नंबरों की तख्तियां लेकर सशक्तिकरण का संदेश देती नजर आई।अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने बताया कि मिशन शक्ति केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनाने का एक व्यापक सामाजिक अभियान है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में

महिला सुरक्षा को लेकर सकारात्मक माहौल बनता है और बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ता है।इस अवसर पर महिला पुलिसकर्मियों ने अपने अनुभव साझा किए और महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा समान अवसरों के प्रति समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया।

अयोध्या जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर चल रहा खेल!

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।भगवान राम की नगरी अयोध्या का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है वजह वही पुरानी, लेकिन चेहरे नए। जिला अस्पताल की ओपीडी में बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता के युवक द्वारा दवाएं लिखे जाने का खुलासा हुआ है। यह घटना न केवल चिकित्सा व्यवस्था की सच्चाई उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस तरह सरकारी संस्थान अब 'स्वास्थ्य सेवा' नहीं बल्कि 'कमीशन सेवा' बन चुके हैं।

-कमरा नंबर 3 की करतूत-जहाँ डॉक्टर नहीं, दवा बेचने वाला लिखता है दवाएँ

सोमवार को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक युवक, संदीप यादव, जिला अस्पताल की बाल रोग ओपीडी (कमरा नंबर-3) में बैठा मरीजों के लिए दवाओं के पर्चे लिखता दिखाई दे रहा है। जांच में पता चला कि यह युवक किसी भी चिकित्सकीय योग्यता का धारी नहीं, बल्कि अस्पताल के सामने एक मेडिकल स्टोर में काम करता है। अस्पताल कर्मियों का आरोप है कि यह युवक डॉक्टरों की मिलीभगत से ओपीडी में बैठता है और उन्हें मोटा

» अनाधिकृत व्यक्ति लिख रहा दवाएं, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं

» डॉक्टरों की मिलीभगत से फिर बेनकाब हुआ मेडिकल माफिया

कमीशन देता है।

यह कोई पहली बार नहीं है जब यह मामला सामने आया हो। इसके पूर्व सीएमएस डॉ. ए.के. सिन्हा के कार्यकाल में भी यही युवक रंगे हाथ पकड़ा गया था और पुलिस को सौंपा गया था। उस वक्त भी पूरे जिले में हड़कंप मच गया था।लेकिन अब वही कहानी दोहराई जा रही है फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार संरक्षण देने वाले चेहरे बदल गए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कुछ डॉक्टरों की सीधी मिलीभगत के बिना यह संभव ही नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति अस्पताल में ओपीडी के अंदर जाकर मरीजों को दवा लिखे।

सूत्रों की माने तो संदीप यादव जैसे लोग इस नेटवर्क की रीढ़ हैं जो न डॉक्टर हैं, न फार्मासिस्ट पर मरीजों की ज़िंदगी से सीधा खेलते हैं।मरीजों का दर्द सरकारी अस्पताल भरोसे का नहीं, भय का ठिकाना बन गया है। मरीज रामलाल ने बताया, हम गरीब लोग सरकारी अस्पताल पर भरोसा करके आते हैं। डॉक्टरों से इलाज की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब बिना डिग्री वाला आदमी दवा लिखता है, तो डर लगता है कि कहीं दवा ही जान न ले ले।एक अन्य मरीज ने कहा यहाँ इलाज नहीं होता, कमीशन चलता है। डॉक्टर और मेडिकल स्टोर की मिलीभगत से अस्पताल मरीजों की मंडी बन चुका है।

नए सीएमएस से उम्मीद टूटी

नए सीएमएस डॉ. राजेश सिंह से लोगों को उम्मीद थी कि अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार, दलाली और अव्यवस्था पर अंकुश लगेगा। लेकिन इस घटना ने उन उम्मीदों को झटका दे दिया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है –

क्या जिला अस्पताल में डॉक्टर और दवा माफिया की यह साझेदारी प्रशासन की आँखों से ओझल है, या फिर सबकी आँखें जानबूझकर बंद कर ली गई हैं?

स्वराज इंडिया का सवाल

›अस्पताल में जब इलाज लिखने वाले ही नकली हों,तो मरीज कहाँ जाए- भगवान भरोसे या माफिया के हवाले

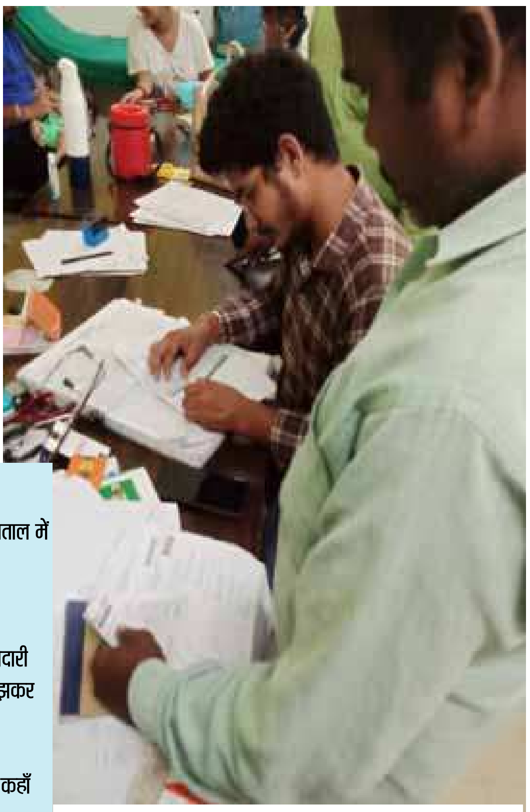

लिख रहा मरीजों को दवाएं अतहर

जिला जज की मध्यस्थता से टला अधिवक्ताओं का आंदोलन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की मध्यस्थता से कोतवाल अयोध्या मनोज शर्मा के खिलाफ चल रहा अधिवक्ताओं का आंदोलन टल गया है। सोमवार को कचहरी में हुई बैठक में अधिवक्ता संघ ने यह निर्णय लिया है। साथ ही 22 अक्तूबर तक कोतवाल को निलंबित करने की डेडलाइन भी दी है। इसके बाद पुन: कोतवाली के घेराव का एलान किया है।

सोमवार सुबह कचहरी खुलते ही कोतवाली अयोध्या के घेराव को लेकर वकीलों में गहमागहमी रही। युवा अधिवक्ता आंदोलन में शामिल होने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार थे। इसी बीच जिला जज ने अधिवक्ता संघ अध्यक्ष को वकीलों के आंदोलन पर विचार करने के लिए अपने कक्ष में बुलाया।अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह की अगुवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियनाथ सिंह, कृपाल चंद्र खरे, सईद खान, वाईवी मिश्रा, कालिका प्रसाद मिश्रा, विजय बहादुर सिंह, संजीव दुबे, राम शंकर यादव व संयुक्त मंत्री राजीव तिवारी आदि ने जिला जज से मुलाकात की।

जिला जज ने अधिवक्ताओं से घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि अधिवक्ता के उत्पीड़न की जांच कराने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा।कोतवाल की संदिग्धता साबित होने पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। जिला जज से वार्ता के बाद वकालतखाना में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। बैठक में आंदोलन स्थगित करने पर सहमति बनी। साथ ही नॉन रेजिडेंट मेंबर की जांच के लिए बनी कमेटी को क्रियाशील बनाने की मांग की गई।अध्यक्ष ने बताया कि दीपोत्सव व दिवाली के कारण 22 अक्तूबर तक के लिए कोतवाली अयोध्या के घेराव का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। अधिवक्ताओं की मांग पूरी न होने पर आंदोलन को गति दी जाएगी। कोतवाल के निलंबन व संपति की जांच होने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। बैठक में प्रभारी मंत्री राजीव तिवारी, पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष राधेश्याम मिश्रा, पूर्व कोषाध्यक्ष राजकपूर सिंह, अधिवक्ता अजय वर्मा, सोमनाथ तिवारी, प्रदीप चौबे आदि मौजूद रहे। उधर, कोतवाली के घेराव के एलान को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मौके पर सिविल पुलिस के अलावा पीएसी बल भी तैनात किया गया था। हालांकि, आंदोलन स्थगित करने निर्णय पर पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली।

खेलते-खेलते मौत की बोलेरो में कैद हुई मासूम जिंदगी

» अयोध्या में तीन साल के अतहर रज़ा की दर्दनाक मौत

» बहन माही जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।भगवान राम की नगरी अयोध्या में सोमवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने लोगों की आंख नम कर दी। सिर्फ तीन साल के मासूम अतहर रज़ा की बोलेरो के अंदर दम घुटने से मौत हो गई, जबकि उसकी पाँच साल की बहन माही की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बाबा बाज़ार थाना क्षेत्र के करौंदी मजरे सैदपुर गांव की है।

बता दें कि गांव में नफ़ीस के घर आज भोज का आयोजन था। घर के बाहर परिवार की कार खड़ी थी। घर के लोग अंदर मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थे, वहीं नफ़ीस का छोटा बेटा अतहर रज़ा (3) अपनी बहन माही (5) के साथ खेलते-खेलते कार के अंदर चला गया।दरवाज़ा बंद हो गया और मासूम दोनों भाई-बहन अंदर फंस गए। गांव के लोग जब तक कुछ समझ पाते, घंटों बीत चुके थे। बच्चों को बेहोशी की हालत में जब कार से बाहर निकाला गया, तो परिजनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोनों को आनन-फानन में सीएचसी सुनवा ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने अतहर को मृत घोषित कर दिया। उसकी बहन माही की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।

थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार आज़ाद के अनुसार, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया, इसलिए पंचनामा भरकर शव को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सरकारी नीति का खामियाजा भुगत रहे सैकड़ों लेखाकार नौकरी छोड़ने को मजबूर

हर तीन साल में विभाग बदल देने से उत्पन्न हो रही समस्या

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। वर्ष 2014-15 में समाजवादी पार्टी के शासन काल में गठित आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय के लेखाकार सरकार की मनमानी से आजिज आकर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, इसी शासन काल में बनी नियमावली के अनुसार तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों (लेखाकार एवं सहायक लेखाकार) का स्थानांतरण उनके मूल विभाग से अन्य विभागों में किया जाने लगा। यही वजह लेखाकारों की समस्या की जड़ बन गई है।

2014-15 से पहले एक लेखाकार अपने ही मूल विभाग की योजनाओं एवं परियोजनाओं से पूरी तरह परिचित रहता था। उसे उस विभाग की बजट व्यवस्था, भुगतान प्रक्रिया तथा वित्तीय नियमों की गहन जानकारी होती थी। लेकिन नई नियमावली लागू होने के बाद हर तीन वर्ष में लेखाकार का स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में कर दिया जाता है। ऐसे में जब तक वह नए विभाग का कार्यकौशल सीखता है, तब तक पुनः उसका तबादला कर दिया जाता है।

इस व्यवस्था के कारण लेखाकार न तो योजनाओं और विभागीय नियमों को पूरी तरह समझ पाते हैं और न ही सुचारु रूप से वित्तीय कार्य पाते हैं। परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है। एक ओर लेखाकार हमेशा भयभीत रहता है, वहीं दूसरी ओर शासकीय कार्य भी प्रभावित

» सपा शासन में बनी नियमावली है समस्या की जड़।

होता है। अहम पहलू यह है कि प्रदेश में तृतीय श्रेणी के अन्य कर्मचारी जैसे–स्टेनो, लिपिक, ड्राइवर, सिपाही आदि का स्थानांतरण उनके विभागों के भीतर ही होता है। वे जिस विभाग में नियुक्त होते हैं, वहीं पूरी सेवा करते हैं। इससे उन्हें उस विभाग की योजनाओं व कार्यशैली का गहन अनुभव हो जाता है और शासन के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। लेकिन लेखाकारों के अंतर-विभागीय स्थानांतरण की नीति के कारण वे नए विभाग की कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ रहते हैं। नतीजा यह होता है कि कई लेखाकार नए विभाग में ज्वॉइन ही नहीं करते, और अगर करते हैं तो संबंधित विभाग की कार्यशैली से अनभिज्ञ होने के कारण अंततः उन्हें प्यारी नौकरी से मजबूरन त्यागपत्र देना पड़ता है।

> किसी नीति के कारण लेखाकार नौकरी छोड़ रहे हैं यह मुझे नहीं मालूम है। न तो हमारे पास ऐसी को जानकारी है, न ही कोई प्रमाणिक दस्तावेज और आज तक किसी ने बताया है। ये बिलकुल भ्रामक सूचनाएं हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
>
> **– गिरीश चंद्र चौबे, अपर निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखापरीक्षा**

वर्तमान सरकार चाहे तो इस अव्यवस्था को समाप्त कर प्रदेश के लेखाकारों एवं सहायक लेखाकारों की इस गंभीर समस्या का समाधान निकाल सकती है।

चुनाव आयोग ने 72 जिलों के डीएम-एसडीएम के तबादले पर रोक लगाई

उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर तक बिना अनुमति नहीं होंगे ट्रांसफर

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर तक 72 जिलों के डीएम व एसडीएम के तबादले चुनाव आयोग की बिना पूर्व अनुमति के नहीं हो सकेंगे। आयोग ने विधान परिषद की 11 सीटों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान के मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मंडलायुक्त भी इस दायरे में आएंगे।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ व इलाहाबाद-झांसी और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद की मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार करने का काम 30

सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। यह प्रक्रिया प्रदेश में कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव छोड़कर अन्य सभी जिलों में चल रही है।

चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की तैयारी के काम में भूमिका निभाने वाले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पदाभिहीत अधिकारी एवं अतिरिक्त पदाभिहीत अधिकारी आदि को भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना अंतिम प्रकाशन यानी 30 दिसंबर तक स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं अगर इस काम में जरूरत के हिसाब से बूथ लेबल अधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा, तो यह रोक उनके मामले में भी लागू होगी।

यहां बता दें कि इन 11 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मंडलायुक्त काम कर रहे हैं। इन मंडलों के अपर आयुक्त (प्रशासन) भी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाए गए हैं। इसके अलावा इन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम, एसीएम, बीडीओ, ईओ व तहसीलदार) भी इस अभियान में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं।

राम को गाली देने वाले वाल्मीकि का अपमान करते हैं: मुख्यमंत्री

» महर्षि की जयंती पर विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ।

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं, वे वास्तव में महर्षि वाल्मीकि का अपमान करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ही श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया था।

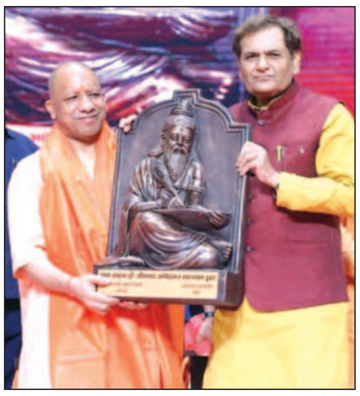

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी लेखनी चलाई, तो उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नारद से प्रश्न किया कि कौन ऐसा चरित्रवान व्यक्ति है, जिसके जीवन पर मैं लिख सकूँ। उन्होंने राम के आदर्श जीवन को धर्म का साक्षात रूप बताया। योगी ने कहा कि जो लोग राम का अपमान करते हैं, वे देश की संस्कृति और आस्था का अपमान करते हैं। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी, ब्रजेश पाठक, डॉ. दिनेश शर्मा और जयवीर सिंह सहित कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि वाल्मीकि समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि वाल्मीकि समाज भाजपा के लिए सिर्फ मित्र नहीं बल्कि परिवार है। वहीं, मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि योगी सरकार दलित और वंचित समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और वाल्मीकि समाज को सम्मान और अवसर देने के लिए समर्पित है।